



अधिक सक्रिय भारतीय राज्य का खाका

यह एडिटरियल 02/12/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Improving the capability of the Indian state”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारतीय राज्य के बहुत बड़े होने लेकिन फरि भी बहुत छोटे होने के वरिधाभास के बारे में चर्चा की गई है और वचिर कयि गयि है क सार्वजनक वस्तुओं एवं सेवओं के वतिरण में इसकी कषमता बढाने से संबद्ध चुनौतयों को कसि प्रकार संबोधत कयि गयि।

प्रलमिस के लयि:

[भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोरड \(SEBI\)](#), [भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#), [भारत के नयितरक और महालेखा परीकषक](#), [केंद्रीय सतरकता आयोग](#), [केंद्रीय अनवेषण बयूरो](#), [भारतीय राषट्रीय राजमार्ग प्राधकिरण](#), [लेटरल एंटरी](#), [मशिन करमयोगी](#)

मेन्स के लयि:

वेबेरयिन राज्य, अन्य राज्यों की तुलना में भारतीय राज्य की स्थिति, भारतीय राज्य के समनुरूप चुनौतयों, आगे की राह

भारतीय राज्य (Indian State) बहुत बड़े होने और फरि भी बहुत छोटे होने का वरिधाभास (paradox of too big and yet too small) रखता है। कसि शहरी कषेत्र में वयवसाय स्थापत करने या घर बनाने के प्रयास में कसि व्यक्त को तुरंत ही एहसास हो जाता है क लाइसेंस, परमटि, मंजूरी और अनुमतयों की भारी संख्या कैसे जीवन को दुशवार बना देती है। यहाँ तक क एक सामान्य नागरक के रूप में भी, कोई भी व्यक्त कभी भी कानून और जटलि नयिमों के सही पक्ष पर होने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता है।

अन्य राज्यों की तुलना में भारतीय राज्य की क्या स्थिति है?

- भारत में 'वेबेरयिन राज्य' (Weberian state) बहुत छोटा है। [G-20 समूह](#) में, भारत में प्रत व्यक्त सविलि सेवकों की संख्या सबसे कम है।
- भारत में कुल रोजगार में सार्वजनक कषेत्र की हसिसेदारी (5.77%) इंडोनेशिया और चीन के मुकाबले महज आधी और यूनाइटेड कगिडम की तुलना में लगभग एक तहार्ड है।
- लगभग 1600 प्रत मिलियन के आँकड़े के साथ भारत में केंद्रीय सरकारी करमयों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 7500 प्रत मिलियन की तुलना में बहुत कम है।
- इसी प्रकार, विकास के समान चरण वाले देशों से तुलना करें तो भारत में कवकितिसकों, शकषकों, नगर नयिजकों, पुलसि, न्यायाधीशों, अग्नशिमन करमयों, खाद्य एवं औषध नरीकषकों और नयिमकों की प्रत व्यक्त संख्या सबसे कम है।

वेबेरयिन राज्य:

- वेबेरयिन राज्य जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर (Max Weber) द्वारा कवकिति एक अवधारणा है। उनके अनुसार, एक आधुनक राज्य प्रशासन एवं वधि की एक प्रणाली है जसि राज्य और वधि द्वारा संशोधत कयि जाता है तथा जो कार्यकारी करमचारयों के सामूहक कयों का मार्गदर्शन करता है; इसी प्रकार कार्यपालक को संवधि द्वारा वनियमि कयि जाता है और यह संघ/एसोसिएशन के सदस्यों (जो आवश्यक रूप से जन्म के आधार पर एसोसिएशन से संबद्ध होते हैं) पर अधिकार का दावा करती है, लेकिन उस कषेत्र में सक्रयि रूप से घटत उन सभी चीजों पर व्यापक दायरे के भीतर जसि पर वह प्रभुत्व रखती है।

भारतीय राज्य के समकष वदियमान प्रमुख चुनौतयों:

- अपर्याप्त राज्य कषमता के कारण आउटसोरसगि सेवाएँ: भारतीय राज्य कर-जीडीपी अनुपात और सार्वजनक वयय-जीडीपी अनुपात जैसे मापन पर अपेक्षाकृत छोटा है। चाहे वह सार्वजनक वस्तुओं के प्रावधान हों, कलयणकारी भुगतान हों या न्याय प्रणाली हों—यह अधशेष के बजाय कमी को प्रकट करता है।
 - अपर्याप्त राज्य कषमता के कारण, केंद्र और राज्यों की सरकारें [प्राथमक सवासथय](#) जैसी सार्वजनक कषेत्र द्वारा बेहतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आउटसोरसगि के लयि बाध्य होती हैं।
- वकृत प्रोत्साहन और कौशल अंतराल: मुख्य समस्याओं में से एक है सार्वजनक संस्थानों द्वारा सृजत वकृत प्रोत्साहन (Perverse

Incentives) और अधिकारियों के बीच कौशल अंतराल (Skill Gap)। इन कारकों ने राजनीतिक कार्यपालिका और सविलि सेवाओं की ठोस नीति निर्माण और प्रवर्तन की क्षमता को नष्ट कर दिया है।

- **शक्तियों का अत्यधिक संकेंद्रण:** भारत में नीति निर्माण और कार्यान्वयन शक्तियों का अत्यधिक संकेंद्रण पाया जाता है।
 - इसके अलावा, कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर नरिणय लेने के लिये अग्रिमि पंक्तों के कर्मियों पर प्रतबंध की स्थिति अवशिवास की संस्कृति और अकुशल कार्यान्वयन के लिये जवाबदेही की कमी को बढ़ावा देती है।
- **टेक्नोक्रेटिक अंतराल:** शीर्ष नीतिनिर्माता तेज़ी से जटिल होती जा रही अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिये टेक्नोक्रेटिक कौशल की कमी दर्शाते हैं। आर्थिक, वित्तीय, अनुबंध और अन्य तकनीकी मामलों से निपटने के लिये पर्याप्त क्षमता के अभाव में केंद्र और राज्य परामर्श फर्मों की नयुक्तों के लिये बाध्य होते हैं।
 - मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार ने पछिले पाँच वर्षों में पाँच बड़ी कंसलटेंसी फर्मों—प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PricewaterhouseCoopers), डेलॉइट (Deloitte), अर्नस्ट एंड यंग (Ernst & Young), केपीएमजी (KPMG) और मैकिनसे (McKinsey) को महत्त्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग के लिये 500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया।
- **बाज़ार नगिरानीकर्ताओं के पास कर्मियों की कमी:** भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) जैसे बाज़ार नगिरानीकर्ताओं के पास पेशेवर कर्मचारियों की कमी है।
 - SEBI के पास लगभग 800 पेशेवर कर्मी हैं, जबकि अमेरिका में इसके समकक्ष अमेरिकी प्रतभूति एवं वनिमिय आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission) के पास कॉर्पोरेट्स के शासन के लिये 4,500 से अधिक वशिषज्ञ हैं।
 - इसी तरह, RBI के पास पेशेवर कर्मचारियों की संख्या 7000 से भी कम है जो यूएस फेडरल रज़िर्व की तुलना में बहुत कम है जसि 22000 पेशेवरों की सहायता प्राप्त है।
- **कमज़ोर नरीकषण और ऑडिट अभ्यास:** एक अन्य समस्या भारत के नयितरक और महालेखा परीकषक (CAG) द्वारा ऑडिट के दायरे का सीमित होना है। यह सरकार में वित्त और प्रशासनिक प्रभागों को नीतगित उद्देश्यों के बजाय नयियों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अधिक प्रोत्साहति करता है।
 - केंद्रीय सत्रकता आयोग (CVC), केंद्रीय अनुवेषण बयुरो (CBI) जैसी अन्य नगिरानी एजेंसियों और न्यायालयों द्वारा संदर्भ को समझे बना प्रव-सूचना का उपयोग करने की प्रवृत्ति ने नौकरशाहों को नीतगित मामलों में वविक का प्रयोग करने से वमिख कर दिया है।
 - अधिकारी प्रायः बड़े अनुबंधों को रद्द कर देना पसंद करते हैं, भले ही वसितार की अनुमति देना बेहतर हो।
 - इसके कारण वसतुओं एवं सेवाओं की खरीद में देरी और अनावश्यक संवदितमक ववाद की स्थिति बनती है।
- **सेवानवृत्त अधिकारियों की समस्याजनक नयुक्तः** नयामक नकियों और न्यायाधिकरणों में सेवानवृत्त अधिकारियों की नयुक्त भी समस्याजनक है। ऐसी नयुक्तियों के लाभार्थियों को पछिली सेवाओं से मलिन वाले पेंशन लाभों से समझौता कयि बना मोटा वेतन प्राप्त होता है।
 - यह सविलि सेवकों को राजनीतिक हेरफेर के प्रतभेद्य बनाता है और उनके सेवाकालीन नरिणयों को प्रभावति करता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की कम प्रभावकारिता:** सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी इसकी प्रभावकारिता को कम करती है। प्रदर्शन से संबद्ध वेतन और प्रोत्साहन योजनाएँ (जैसे बोनस), जो नजी क्षेत्र में अच्छी भूमिका नभिताती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक प्रभावकारी नहीं हैं।
 - भारत में वशिष रूप से छठे वेतन और सातवें वेतन आयोग द्वारा पर्याप्त वेतन वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन बहुत अधिक है (नौकरी की प्रकृति के अनुपात से वसिगत)।
 - शीर्ष सत्र को छोड़कर, अधिकांश कौशल स्पेक्ट्रम के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन नजी क्षेत्र के वेतन से बहुत अधिक है। यह नयुक्तियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सरकारी नौकरियों को सभी के लिये अत्यधिक आकर्षक बनाता है, चाहे वह सामाजिक रूप से प्रेरति हो या नहीं।

आगे की राह:

- **पृथक नीति निर्माण और कार्यान्वयन:** ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कनीति निर्माण एवं कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारियों को पृथक करने से नषिपादन में तेज़ी आती है और नवाचारों को बढ़ावा मलितता है, जसिसे कार्यक्रम स्थानीय संदर्भों के लिये बेहतर अनुकूल हो जाते हैं।
 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नषिपादति करने का कार्य सौंपा गया है जबकि नीतगित नरिणय मंत्रालय स्तर पर कयि जाते हैं। इस व्यवस्था से देरी और लागत वृद्धि में भारी कमी आई है।
- **वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्यायोजति करना:** उस दुषचकर को तोड़ा जा सकता है जसिमें कमज़ोर प्रत्यायोजन और अपर्याप्त राज्य क्षमता एक-दूसरे को पोषति करते हैं। इसके लिये वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों (उनके उपयोग के लिये स्पष्ट रूप से परभाषति प्रकरियों के साथ) को अग्रिमि पंक्तों के पदाधिकारियों या नचिले स्तर के नौकरशाहों को सौंपना उपयुक्त होगा।
- **पार्श्व प्रवेश संस्कृति का सामान्यीकरण:** मध्य और वरषिट स्तर पर एक संस्थागत एवं नयिमति पार्श्व प्रवषिटि (Lateral Entry) सविलि सेवाओं के आकार और टेक्नोक्रेटिक अंतराल को दूर करने में मदद कर सकती है।
 - गैर-आईएसएस सेवाओं (जैसे भारतीय राजस्व, आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं) के योग्य अधिकारियों को उच्च-स्तरीय पदों पर उचति अवसर मलितना चाहिये, यदा उनके पास आवश्यक प्रतभा एवं वशिषज्ञता है।
 - इसके साथ ही, वभिन्न स्तरों के सविलि सेवकों को मशिन कर्मयोगी (सविलि सेवा क्षमता निर्माण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम) के तहत वषिय-वशिषिट प्रशिक्षण प्रदान कयि जा सकता है।
- **नयामक एजेंसियों को संवेदनशील बनाना:** पंचाट और अदालती नरिणयों के वरिद्ध अपील करना अधिकारियों का डिफॉल्ट मोड ही बन गया है, जसिसे सरकार सबसे बड़ी याचिकाकर्ता बन गई है।
 - इस परदृश्य से निपटने के लिये नरीकषण एजेंसियों को नीतगित नरिणयों के संदर्भ की सराहना करने के लिये संवेदनशील बनाया जाना चाहिये। उन्हें वास्तविक नरिणयों के साथ-साथ उनके वकिलों से जुड़ी लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिये।
- **सेवानवृत्त की आयु बढ़ाना:** नयामक नकियों में सेवानवृत्त अधिकारियों की नयुक्ति प्रायः सविलि सेवकों को राजनीतिक हेरफेर के प्रतभे

भेद्य/संवेदनशील बनाती है।

- सभी सरकारी नौकरियों के लिये सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने और सभी नयिकृतियों के लिये एक पूर्ण ऊपरी सीमा का निर्माण करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र नयोजन में सुधार लाना: सार्वजनिक क्षेत्र को आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों को आकर्षित करना चाहिये ताकि वे सामाजिक भलाई में योगदान कर सकें।
 - रोजगार सुरक्षा और बेहतर कार्यशील परस्थितियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिम और कौशल-समायोजित वेतन नज्जि क्षेत्र की तुलना में कम होना चाहिये।
 - इसका एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि भविष्य के वेतन आयोग द्वारा मध्यम वेतन वृद्धिलागू की जाए और सरकारी नौकरियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में कमी लाई जाए।
- नज्जि क्षेत्र में रोजगार सृजन: उच्च आर्थिक विकास, जो नज्जि क्षेत्र में आकर्षक रोजगार अवसर उत्पन्न करता है, सरकारी नौकरियों को उन लोगों के लिये कम आकर्षक बना देगा जो प्राप्त वेतन पर अधिक विचार करते हैं। यह भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और सामाजिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों के सरकार में शामिल होने की संभावना को बढ़ा सकता है।

नषिकर्ष:

भारत के शासन संबंधी वरिधाभास (governance paradox) के लिये व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे नीति निर्माण को कार्यान्वयन से अलग करना, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को सशक्त बनाना और सेवानिवृत्त की आयु को समायोजित करना। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सामाजिक भलाई के लिये प्रतर्बिद्ध लोगों को आकर्षित करना है। भारत अपनी राज्य मशीनरी को पुनर्जीवित कर प्रभावी शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में उभर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय राज्य के वर्तमान नौकरशाही ढाँचे में वदियमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से नपिटने के लिये कनि सुधारों की आवश्यकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. "आर्थिक प्रदर्शन संस्थागत गुणवत्ता एक नरिणायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (

description: भारतीय राज्य (Indian State) बहुत बड़े होने और फरि भी बहुत छोटे होने का वरिधाभास (paradox of too big and yet too small) रखता है। कसि शहरी क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने या घर बनाने के प्रयास में कसि व्यक्तिको तुरंत ही ए